(iii) The remaining power (73 per cent) is distributed between the States of the Region (including the "Home State") on the basis of Central assistance given to various States in the Region during the last five years and on the basis of consumption of electricity in the States in the Region in the last five years, the two factors being given equal weightage.

Import of paper

1512. SHRI RAJNI RANJAN SAHU: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether Government propose to import paper and kraft paper in view of its high prices in the country;

(b) if so, what is the quantity value thereof; and

(c) if not, what are the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI M. ARUNACHALAM): (a) No, Sir. There is no such proposal under consideration of the Government at present.

(b) Does not arise.

(c) Except for certain speciality papers, which are allowed for import, indigenous production of paper and paper board is considered adequate to meet the current demand.

Collapsing of newly constructed bottling plant of Bharat Petroleum at Bokarbida, Uran (Maharashtra)

1513. SHRIMATI SURYAKANTA JAYAWANTRAO PATIL: Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a newly constructed LPG bottling Plant of Bharat Petroleum at Bokarbida, Uran (Maharashtra) costing Rs. 135 crores collapsed, near another tank where 100 employees were on duty; and

(b) if so, what are the details thereof and what action has been taken against the officials responsible for this?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (SHRI BRAHM DUTT): (a) No, Sir.

(b) Does not arise in view of (a) above.

भारत में प्राकृतिक गैस के उत्पादन के लिये विश्व बैंक द्वारा ऋण

1514. **श्री विश्वासराव रामाराव पाटिल :** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व बैंक ने भारत में प्राकृतिक गैस के उत्पादन में सुधार लाने के लिये भारत को 29.5 करोड़ डालर का ऋण देने की घोषणा की थी ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है और यह धनराशि किस प्रकार खर्च की जायेगी ; और

(ग) इस समझौते के निबन्धन और शर्तें क्या क्या हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) और (ख) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की कुछ पश्चिमी तटवर्ती और अपतटीय गैस विकास परियोजनाओं के लिए भारत सरकार को स्वीकृत 29.5 करोड़ अमरीकी डालर के ऋण के लिए विश्व बैंक के साथ करारों पर अप्रैल, 1988 में हस्ताक्षर किए गए हैं ।

(ग) यह ऋण आई.बी.आर.डी. की मानक शर्तों के आधार पर होगा, जिसमें विश्व बैंक का अपनी उदार लागत के अनुसार ब्याज को परिवर्तनीय दर शामिल है। इसके अतिरिक्त, ऋण की राशि के अवितरित अंश पर 0.75 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से बचत प्रभार भी लगेगा। यह ऋण 5 वर्ष की रियायती अवधि सहित 20 वर्षों में अदा किए जाएंगे।

Cooking gas facility in cities of Tamil Nadu

1515. SHRI K. V. THANGKABALU: Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to state:

(a) what is the number of cities in Tamil Nadu where cooking gas facility has been provided so far ; and

(b) by what time this facility will be provided to the remaining cities in Tamil Nadu?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (SHRI BRAHM DUTT): (a) At present 123 towns/cities in Tamil Nadu have been provided with LPG facility.

(b) The Oil Industry, upto its 1988-89 LPG Marketing Plan, proposes to establish 38 more LPG distributorships in 4 new towns/cities of Tamil Nadu. In view of the various steps which precede the actual commisioning of each LPG distributorship, it is not possible to indicate the exact time by when these will be commissioned.

राजस्थान में लघु तथा मझोले उद्योगों की स्थापना करने हेतु प्रार्थना-पत्र

1516. **श्री संतोष बागड़ोदिया :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान राजस्थान में लघु तथा मझोले उद्योग की स्थापना करने हेतु कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए; और

(ख) कितने उद्योगों के सम्बन्ध में "आशय-पत्र" जारी कर दिए गये हैं और उनका ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) लघु उद्योग स्थापित करने के लिए आवेदन राज्य सरकार में उद्योग निदेशक द्वारा सीधे ही प्राप्त किये जाते हैं और केन्द्रीय रूप से इस बारे में कोई सूचना नहीं रखी जाती। वर्ष 1986, 1987 और 1988 के दौरान राजस्थान में उद्योग स्थापित करने के लिए जारी किए गए आशय पत्रों, लाइसेंसमुक्त योजना के अधीन पंजीकृत योजनाओं और तकनीकी विकास महानिदेशालय में पंजीकृत योजनाओं की संख्या नीचे दी गई है :-

वर्ष	जारी किये गये आशय पत्रों की संख्या	पंजीकृत योजनायें	
		डी०एल० आर०	डी०जी० टी०डी०
1986	37	69	53
1987	41	99	57
1988	24	43	46

जारी किये गये आशय पत्रों के ब्यौरे भारतीय निवेश केन्द्र द्वारा प्रकाशित मासिक न्यूजलैटर में उपलब्ध हैं। इसकी प्रतियां संसद पुस्तकालय को भेजी जाती हैं।

Revival of the Central Investment Subsidy Scheme

1517. SHRI M. VINCENT:
SHRI AJIT P. K. JOGI:

Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state :

(a) what are the 'revolutionary changes' in the industrial policy that were introduced during the last financial year;